(c) if so, what are the details thereof stating—

(i) the annual killings of tuskers since 1980,

(ii) the estimated value of the tusks poached since 1980, and

(d) whether Government propose to launch project elephant on the lines of project tiger to save the elephants population?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI) (a) to (c) The information is being collected and would be placed on the Table of the House

(d) Yes sir,

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजना के अधीन सड़कें तथा पुल

786. **श्री राधा किशन मालवीय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय योजना के अधीन कितनी सडके तथा पुल है तथा वर्ष 1990–91 के दौरान कितनी सड़को तथा पुलो की मजूरी दी गई है; और

(ख) इस सबध मे मध्य प्रदेश को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल-संसाधन मंत्री, साथ मे जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाडिया) (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश मे सडको और पुलो की चालू केन्द्रीय योजनाओ की संख्या निम्नलिखित है :–

	सडक	पुल
राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	136	53
आर्थिक और अतर्राज्यीय महत्व की सड़कें	—	—
केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर एफ.)	1	—

इसके अतिरिक्त 1990–91 के दौरान निम्न संख्यक योजनाओ का अनुमोदन किया गया है :—

राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास	15	—
आर्थिक और अंतर्राज्यीय महत्व की सडके	—	—
केन्द्रीय सडक निधि	—	—

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गो के विकास के लिए 1990–91 के दौरान मध्य प्रदेश के लिए 21 00 करोड रु का आवटन किया गया है जिसमे चल रहे कार्य और चालू वित्त वर्ष मे अनुमोदित कार्य शामिल है। आर्थिक और अतर्राज्यीय महत्व की योजना के अतर्गत कोई राशि निर्धारित नही की गई है । केन्द्रीय सडक निधि के अतर्गत निधिया राज्य के लिए अनुमोदित योजनाओ की कुल लागत विगत मे रिलीज की गई निधियो, प्रचालनात्मक स्वीकृतियो की बकाया राशि और बजटगत प्रावधान को ध्यान मे रखकर रिलीज की जाती है । उपर्युक्त मानदडो को ध्यान मे रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार को हकदारी के अनुसार केन्द्रीय सडक निधि के अतर्गत आने वाले कार्य के लिए 1990–91 के दौरान आवटन हेतु 50 00 लाख रु की राशि निर्धारित की गई है।

मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों में तारघर की सुविधा

787. **श्री राधा किशन मालवीय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश मे कितने ऐसे जिला मुख्यालय है जहा तारघर को सुविधा है; और

(ख) क्या सरकार ने एक निश्चित अवधि के अन्दर सभी जिला मुख्यालयों मे तारघर खोलने की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिला मुख्यालयो मे तारघर सुविधा मुहैया करवा दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

नये डाकघर तथा शाखा डाकघरों का खोला जाना

788. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 मे कितने नये डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) इन डाकघरो तथा उनके कर्मचारियों पर खर्च की जाने वाली राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) 1990–91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 200 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्डो को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से संशोधित किया जा रहा है। जब तक मौजूदा प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है तब तक राज्यवार डाक नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप नही दिया जा सकता है। नए मानदण्ड निर्धारित हो जाने के बाद बजटीय प्रावधानो सहित राज्यवार ब्यौरो को अंतिम रूप दिया जाएगा। सयोग से योजना आयोग ने डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए 1990–91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपए के परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है जिसके अन्तर्गत नए डाकघर खोलने का कार्यक्रम भी आ जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की रिपोर्ट जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाने की संभावना है।

Procedure for environment clearance

789. SHRI JITENDRABHAI LABHSHANKER BHATT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have submitted a set of proposals for rationalisation of environment clearance procedures which aim at "expanding the role of the Ministry" as reported in the Deccan Herald of 1st September, 1990, and

(b) if so, the details of improved procedure for environment clearance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Proposals for rationalisation of environmental impact assessment procedure have been under consideration with the following salient features:—

—Making environmental impact assessment a statutory requirement;

—Uniform coverage of both private as well as public sector projects;

—Delegation of powers for environmental clearance of certain categories of projects to state agencies.

The primary objective of these proposals is to rationalise the procedure rather than expand the role of the Ministry.

मंडल आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों को हुई क्षति

790. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के विरोध में छात्रो द्वारा किए